SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to take steps to release Indian fishermen who are currently in Pakistani jails

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं आपकी इजाज़त से गुजरात के मछुआरों का एक इश्यू उठाना चाहता हूँ।

सर, हमारे गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ है। आज भी 156 मछुआरे पाकिस्तान की कैद में हैं। पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया है, तो maximum imprisonment is for three years. वे तीन साल से ज्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं, परन्तु तीन साल बीत जाने के बाद भी वे लोग वहीं पर कैद में हैं। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा कर ले जाती है और जो फिशिंग बोट्स वहाँ पर रहती हैं, उनके अन्दर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुराकर ले जाते हैं। इसलिए अगर वे फिशिंग बोट्स वापस आती भी हैं, तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती हैं। इसी के चलते उनकी कुछ माँगें थीं और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो हम उनसे मिले और हमने तीन-चार चीजें की थीं। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनको पुनः शुरू किया जाए।

हमने एक काम यह शुरू करवाया था कि अगर यहाँ से मछुआरे की फैमिली उसे डाक भेजेगी, खत लिखेगी, तो वह उसे वहाँ कैद में मिलेगा और जो मछुआरा पाकिस्तान की कैद में है, वह वहाँ से अपनी फैमिली को खत लिख सकता था। वह काम शुरू हुआ था। इस सरकार की रिजीम में वह बन्द हो गया है। एक परिवार का बन्दा किसी दुश्मन देश की कैद में है और उसके

हाल-चाल भी परिवार वाले नहीं जान सकें, तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। इसलिए वह काम पुनः शुरू होना चाहिए।

हमने दूसरा काम यह शुरू करवाया था, सरकार ने उस वक्त शुरू किया था कि जिस भी मछुआरे की फिशिंग बोट वहाँ गई और उस फिशिंग बोट को वहाँ रख लिया गया, तो उसके लोन की किश्तों को रोक दिया जाता था और उसको फिशिंग बोट के लिए सब्सिडी दी जाती थी। वह भी आज शुरू नहीं हुई है।

तीसरी जो माँग थी, जो वहाँ पर हुई थी, उसकी राशि बहुत कम है। परिवार का जो भी कमाने वाला व्यक्ति है, वह तो कैद में चला गया और जनरली किसी फिशिंग बोट में परिवार के जितने भी मेल मेम्बर्स या कमाने वाले लोग होते हैं, वे साथ में होते हैं। जब वे चले जाते हैं, तो इधर सिर्फ बच्चे और महिलाएँ बचती हैं। तो उनको कुछ सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए। उस वक्त की सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए दी थी। उन्हें जीपीएस दिया गया था, जिससे मछुआरे को भी पता चले कि मैं अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, तो यह मुझे वापस कर देगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गुजरात गवर्नमेंट थी। सीएंडएजी ने कहा कि भारत सरकार ने जो पैसे एक फिशरमेन की सेफ्टी हेतु जीपीएस सिस्टम के लिए दिए हैं, * और इसी वजह से जीपीएस का सिस्टम चल ही नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यह राशि भारत सरकार की थी, सीएंडएजी ने भी यह कह दिया है, तो हम मानते हैं कि यह बहुत सीरियस चीज़ है, इसलिए सीबीआई के जरिए इसकी जाँच भी होनी चाहिए।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SANDOSH KUMAR P. (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need to provide support to the farmers who are custodians of traditional seed varieties in India

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me time to speak on this very important issue pertaining to farmers who are custodians of traditional seed varieties.

Sir, India had rich agro diversity. Scientist, Dr. Richharia, had documented thousands of valuable paddy varieties which were evolved and selected by our ancestral farmers. Though Green Revolution paradigm eroded this rich agro diversity wealth, yet our farmers continued to conserve some of them in their farms. Despite great logistical and financial hardships, these farmers are conserving thousands of varieties of different crops. Some of them have been recognized with Genome Saviour Award, which is a welcome recognition for their contribution. We also need to remember the role of women farmers.

Sir, the Government needs to identify and support such seed savers and train them for maintaining genetic purity of seeds' characterization and cataloguing under a scheme, providing infrastructure facilities and stipends. Surely, the Government will agree with me that *desi* seed varieties and the farmers who conserve them need support so that it can then become a basis for spread of organic and natural farming.

Late Shri George Fernandes, who led an aggressive campaign against signing of GATT and WTO Treaty, is an inspiration for me. I am proud that in 2009, when regulator, GEAC, approved BT Brinjal, it was again my party leader, Shri Nitish